

BIHAR
FOUNDATION
Bonding • Branding • Business



Phone: +91 612 2547371

E mail: pro@biharfoundation.in

<https://biharfoundation.bihar.gov.in/>

बिहार सरकार

बिहार आज

(बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति)

दिनांक — 19.08.2020

6th Floor, Indira Bhawan, RCS Path, Patna - 800001

14 साल के बाद नियोजित शिक्षकों को मिली सौगात

कड़ा संघर्ष

संवाददाता > पटना

साढ़े तीन लाख से अधिक बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर लंबा आंदोलन चलाना पड़ा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आपके लिए कुछ करेंगे भी तो हम ही. विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर सरकार जल्द ही नीतिगत निर्णय लेगी. इसी के अनुरूप मंगलवार को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी ली गयी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि पिछले पांच सालों में नियोजित शिक्षकों के वेतन में करीब साठ फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. उन्हें मेडिकल भत्ता, आवास भत्ता और महंगाई भत्ता पहले से दिया जा रहा है. इस बार तबादला और पितृत्व अवकाश का भी लाभ दिया जा रहा है. गौरतलब है कि 2006 दिसंबर से 2007 मार्च के बीच नियोजित शिक्षकों की पहली भर्ती उस समय की नियमावली के तहत हुई थी. तब पहला संघर्ष इस बात को लेकर था कि उनकी नियुक्ति पहले से चले आ रहे शिक्षक पदों को डाइंग कैडर घोषित करके की गयी थी. इससे संबंधित तकनीकी अड़चनों से शुरू हुआ संघर्ष 2009 में चरम पर पहुंचा. इसके बाद 2012, 2015 और 2017 में भी धरना

विशेष : नयी सेवा शर्त में शिक्षकों के वेतनमान में पंद्रह फीसदी की बढ़ोतरी के प्रावधान से नियोजित शिक्षकों को 2200 से चार हजार के बीच फायदा होगा.

प्रदर्शन में भी हुआ. इन सभी आंदोलनों के दौरान सरकार ने आश्वासन दिये. कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गये. नियोजित शिक्षकों का संघर्ष लगातार जारी रहा.

वर्ष 2015 में बड़ी हड़ताल हुई. हालांकि, स्कूल बाधित नहीं किये गये. तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही के हस्तक्षेप के बाद वेतन बढ़ाने को लेकर सहमति बनी. हालांकि अपेक्षित वेतनमान नहीं बढ़ा. सातवां वेतनमान की इच्छा रह गयी. हालांकि इस आंदोलन के बाद सरकार ने एक अलग से पे मेट्रिक्स और नया वेतनमान तय किया. इसमें नियोजित शिक्षकों को 5500-20200 का वेतनमान तय हुआ. साथ ही ग्रेड पे प्रारंभिक और मध्य शिक्षकों 2400-2600-2800 तय किया गया. सबसे अंतिम आंदोलन पिछली साल भी हुआ. यह दौर 2020 के शुरुआती महीनों में भी चला. दूसरी ओर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि इससे राज्य के नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. क्योंकि, राज्य सरकार ने विधानमंडल के अंदर व सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान दिया जायेगा.

मखाना को जल्द मिलेगा जीआइ टैग : मुख्यमंत्री



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य.

○ हमलोगों का सपना है कि हर भारतीय थाल में एक बिहारी व्यंजन जरूर हो

संवाददाता ▶ पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के खास उत्पाद मखाना को जल्द ही अलग पहचान मिलेगा. जीआइ टैग के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. उन्होंने कहा कि मखाना से देश भर को लगाव है, इस पर और काम करने की जरूरत है. मंगलवार को 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 268 करोड़ की लागत से बिहार कृषि विवि, सबौर के प्रशासनिक भवन व शैक्षणिक सह प्रयोगशाला भवनों का उद्घाटन के मौके पर कहा कि जर्दालु आम, कतरनी चावल, मगही पान व शाही लीची को पेटेंट कर जीआइ टैग प्राप्त किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि महाविद्यालय सबौर देश के पहले पांच कृषि महाविद्यालयों में से एक है. उन्होंने कहा कि डॉ राजेंद्र प्रसाद कृषि

विवि पुसा जो कि अब डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि के रूप में परिणत हो गया है, यह 1905 में समस्तीपुर जिले के एक गांव में यूएसए के हेनरी फिक्स के सहयोग से इंफिरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तीन कृषि रोड मैप बनाये गये हैं. इससे फसलों की उत्पादन व उत्पादकता दोनों बढ़ी है. कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुष क्रांति लायी गयी गयी और उससे बढ़ते हुए रजत क्रांति यानी अंडे का उत्पादन भी हुआ है. राज्य में धान, गेहूं, मक्के, फल, सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि 2012 से कृषि स्नातक की पढ़ाई में दो हजार प्रति माह छात्रवृत्ति व छह हजार प्रति वर्ष किताबें खरीदने के लिए राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार कृषि विवि सबौर अब राष्ट्रीय रैंकिंग में 18वें नंबर पर आ गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गयी जल जीवन हरियाली अभियान पर 24,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कोरोना से लड़ने को मजबूत इच्छाशक्ति चाहिए: अवधेश



पटना. बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. इससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत इच्छाशक्ति को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कोरोना संक्रमितों के लिए और लाकडाउन के दौरान मजदूरों की मदद करने के लिए बिहार फाउंडेशन के विशेष कार्य पदाधिकारी और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा का स्वागत किया. उन्होंने कोरोना के दौरान महसूस किए गये अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनके साथ परिवार के आठ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया

था. लेकिन, इच्छाशक्ति की बढ़ोतरी इस बीमारी पर विजय पायी है. उपेंद्र महारथी कला संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे गरीब बिहारी, दिहाड़ी मजदूरों को राज्य सरकार के आदेश अनुसार मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, गुजरात, वाराणसी में सामाजिक संगठन एवं स्वयं सेवक के साथ समन्वय बना कर 12 लाख लोगों को भोजन राशन तथा रहने की सुविधा दी गयी. बिहार फाउंडेशन द्वारा कोरोना विजेताओं के अनुभवों पर निर्मित इस वीडियो को प्रस्तुत किया गया. कार्यक्रम में विधान परिषद के सचिव विनोद कुमार भी मौजूद थे.

राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव : सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को संवाद करेंगे

देश देखेगा मुंगेर के सामुदायिक शौचालय का खास मॉडल

हिन्दुस्तान

खास

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार के सामुदायिक शौचालय का बेहतर प्रबंधन पूरा देश देखेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय की कैटेगरी में मुंगेर नगर निगम के टॉयलेट का चयन किया गया है। इसका उपयोग 45 परिवार करते हैं। स्वच्छता के लिए भी उन्होंने सामुदायिक प्रबंधन किया है। इस सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने

वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को संवाद करेंगे। यह उस दिन होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव का हिस्सा होगा। दो अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ स्वच्छता का कारवां अब एक अभियान बन चुका है। इस अभियान में पूरे देश की भागीदारी सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित करती है। स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। इनकी घोषणा 20 अगस्त को होगी। इस आयोजन को स्वच्छता महोत्सव नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता परीक्षा के विजेताओं को



शौचालय की स्वच्छता के लिए हर परिवार देता है 40 रुपए

मुंगेर के नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में अपने निकाय के चयन पर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि जिस सामुदायिक शौचालय को पुरस्कृत किया जा रहा है, उसे 45 परिवार प्रयोग करते हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर हैं। शौचालय में सफाई रहे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके, इसके लिए प्रयोग करने वाले परिवार हर महीने 40-40 रुपए देते हैं। परिवारों के कार्ड बना दिए गए हैं। एकत्रित होने वाली राशि से शौचालय पर तैनात कर्मियों को वेतन मिलता है।

पीएम से संवाद के लिए हुआ रिहर्सल

पीएम मोदी 20 को मुंगेर के सामुदायिक शौचालय के लाभुकों से भी बात करेंगे। जानेंगे कि शौचालय के उपयोग से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। उस आयोजन की तैयारी का सिलसिला मंगलवार को चला। ड्राई रन कराया गया। सोमवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग और मुंगेर नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे।

पुरस्कृत करने के साथ ही इस अभियान के लाभुकों से भी बात करेंगे। इसके

लिए अलग-अलग कैटेगरी में बेहतर कार्य करने वाले देशभर के कुछ

निकायों को चुना गया है। बिहार से इस सूची में मुंगेर नगर निगम का नाम है।

हिन्दुस्तान | पृष्ठ सं० - 2

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

क्र०स०	विदेश अवस्थित चैप्टर
1	कतर
2	जापान
3	यू०ए०ई०
4	बहरीन
5	कनाडा
6	ऑस्ट्रेलिया
7	दक्षिण कोरिया
8	हाँग कॉंग
9	सिंगापुर
10	न्यूजीलैंड
11	यू०एस०ए०
12	सऊदी अरब

क्र०स०	देश अवस्थित चैप्टर
1	मुम्बई
2	चेन्नई
3	कोलकाता
4	हैदराबाद
5	नागपुर
6	वाराणसी
7	पुणे
8	गुजरात
9	गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन से जुड़ें

बिहार फाउन्डेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निर्बधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है. वर्तमान में बिहार फाउन्डेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउन्डेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें:- <https://biharfoundation.bihar.gov.in>.